

बैटरी उत्पादन के लिए पीएलआई

प्रोत्साहन

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश में बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके तहत बैटरी भंडारण के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18 हजार 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को भी मंजूरी दी है। इससे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना

योजना

- प्रधानमंत्री की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना ने लगाई मुहर
- 18100 करोड़ रुपये वाली उत्पादन योजना को मंजूरी

एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने कहा कि इसमें 45,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी के तहत बिजली को इलेक्ट्रो-केमिकल या रसायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।



जरूरत पड़ने पर इसे फिर बिजली में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा कई क्षेत्रों में होगा क्योंकि, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सोलर पावर प्लांट में इस तरह की बैटरी की जरूरत होती है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) से देश में उत्पादन बढ़ेगा। इससे आयात कम होगा।